श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : उपसभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने जो अपने स्टेटमेंट में बात बताई है, उसमें गुजरात के लिए पावर स्टेशन लगाने की क्या-क्या योजनाएं हैं, वह बताइये।

उपसभापति : अभी तो क्वश्चन आवर खत्म हो गया। आप इनको लिख कर भिजवा दीजिएगा।

You may send the information in writing to the hon. Member. Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Installation of Amguri Power Project

*388. SHRI BHADRESHWAR GOHAIN: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) what is the reason for government's delaying site installation of the Amguri Power Project in Assam; and

(b) by when the physical progress of the project at site will be seen by the people, and the expected time for commissioning the same?

THE MINISTER OF POWER (SHRI N.K.P. SALVE): (a) and (b) The scheme for installation of a gas-based combined cycle power plant at Amguri in Assam, with a capacity of 360 MW, was sanctioned by the Planning Commission in August, 1991 at an estimated cost of Rs. 408.25 crores for implementation in the State Sector. The construction work on the project has not commenced as financing arrangements for the project could not be firmed up. The State Government have since decided to execute this project in the private sector. A Memorandum of Understanding was signed on 10-6-1993 between the Assam State Electricity Board and M/s N.E.I. Inc. (USA) for the purpose. The time for completion can be estimated after completion of all the formalities and placement of order for plant & equipment.

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का पुनर्जीवन

*389. डा० जितेन्द्र कुमार जैन :
श्रीमति सुषमा स्वराज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जुलाई, 1993 के "दि इकोनोमिक टाइम्स" में "फर्स्ट रिवाइव बी.आई.एफ.आर." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि हाल ही में एक समिति ने सरकार से औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में कतिपय सुधार करने की सिफारिश की है ;

(ग) यदि हां, तो प्रमुख सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार द्वारा इन सिफारिशों को स्वीकार कर इन्हें क्रियान्वित करने की कोई योजना बनाई गई है, और

(घ) यदि उपरोक्त (ग) का उत्तर "हां" हो तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) :

(क) जी, हां।

(ख) से (घ) औद्योगिक रुग्णता तथा निगमित पुनर्गठन पर एक समिति मई 1993 में डा. ओमकार गोस्वामी की अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी, जिसने जुलाई 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं :

(i) रुग्णता का जल्दी पता लगाना,